श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्न सं० 372 जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है कि मैं आर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। श्री प्रकाशवीर शास्त्री।

प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक

+

*352. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मणियंगाडन :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :

क्या शिक्षा मंत्री 12 फरवरी, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या उन राज्य सरकारों को जिन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनक्रम नहीं बढ़ाये हैं, कुछ लिखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां मार्च, 1964 में समस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें अध्यापकों के वेतन बढ़ाने की आवश्यकता और इस योजना के लिए उपलब्ध केन्द्रीय सहायता की ओर उनका ध्यान दिलाया गया था।

(ख) वेतनमानों में संशोधन करने का निर्णय करना सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

English translation also.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, इसका तर्जुमा हो जाता है प्रश्नोत्तर के समय

अध्यक्ष महोदय : हां, तर्जुमे की जरूरत नहीं है।

Shri M. C. Chagla: I thought, I had to read the English answer also.

Shri Ram Sewak Yadav: No, no.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जैसा अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि पांच राज्यों को उन्होंने इस प्रकार का संकेत दिया था कि वे प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन मान बढ़ायें। मैं जानना चाहता हूं कि वे पांच राज्य कौन-कौन से हैं और उन पांचों राज्यों पर आपके संकेत देने के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई है।

Shri M. C. Chagla: I wrote a letter to all the Chief Ministers on the 21st March, 1964, pointing out the importance of reviewing the situation with regard to the conditions of service and emoluments of the teachers and also the disparity that exists between teachers in Government schools and in private schools. I have received answers from Bihar, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh and West Bengal only. If my hon. friend wants it, I shall read out briefly the answers received from the States; or, if you like, I can place a statement on the Table of the House.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पिछले अधिवेशन में शिक्षा मंत्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि वेतनों के क्रम में सब से कम वेतन सारे भारत में उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी शिक्षा मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कुछ लिखा है? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

Shri M. C. Chagla: As I have said, I wrote to the Chief Minister of every State. Only five States have replied.

The position with regard to U.P. is this. The scales of pay were revised in the Second Plan. There has been a slight improvement in the Third Plan. There is, however, a difference of about Rs. 15-20 in the dearness allowance paid to primary teachers and other government servants drawing the same salary. This position is, therefore, the same as that in Bihar. On financial grounds, the State Government has not been able to equalise the dearness allowance paid to primary teachers and other Government servants.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न विश्वविद्यालय या हायर सैकिन्डरी स्कलों के अध्यापकों के सम्बन्ध में नहीं था । मेरा प्रश्न प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के सम्बन्ध में था । मैं उनके सम्बन्ध में जानना चाहता था ।

श्री मु० क० चागला : मैं ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के बारे में ही जवाब दिया है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : जो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक हैं उनको वहां वेतन बहुत थोड़ा मिलता है, वहां उनको उनके स्थान से दूर दूर भेज दिया जाता है इसलिए उनका खर्च और उ के घर का, बीबी बच्चों का खर्च दुगुना हो जाता है जो कि उनके लिये असह्य है । क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यह निर्देश देगी कि उन प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको को उनके स्थान पर अथवा उसके पास के स्थानों पर नियुक्त किया जाए ?

Shri M. C. Chagla: This is an important problem, and we are considering it, that is, the question about the transfer of teachers. But it is very difficult. It is part of either the disability or the advantage of being a government servant that one is liable to transfer.

श्री क० ना० तिवारी : मंत्री महोदय ने बताया कि बिहार से रिपोर्ट आ गई है, लेकिन वहां के अखबारों में जो समाचार छप रहे हैं उनसे पता चलता है कि अभी तक वेतन नहीं बढ़ा है और बिहार के अध्यापक स्ट्राइक करने वाले हैं । क्या सरकार इसके बारे में बताने की कृपा करेगी ?

Shri M. C. Chagla: My information is that they had threatened a strike, but in view of the assurance given, the strike has been put off.

श्री ओंकार लाल बेरवा : एक प्रकार के स्कूल केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा तथा ग्राम पंचायतों द्वारा चलाए जाते हैं । क्या इनके वेतन क्रमों को एक सा बनाए रखने का यत्न किया जा रहा है ?

Shri M. C. Chagla: We are trying to bring about uniformity. It is not easy, but that is our attempt, that is our objective and that is our target.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सारे देश में जिला परिषदों के मातहत छोड़ा हुआ है । जिला परिषदों ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे कि उनके वेतन क्रमों में आमूल चल परिवर्तन हो सके और इन अध्यापकों की तीन तीन जगह की मातहती करनी पड़ती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई उपाय किया जा रहा है कि इसके बजाय उनकी तरक्की एक ही जगह हो सके ?

Shri M. C. Chagla: My answer is the same. The difficulty is that the States feel that they have no finances. I have done my best. I have impressed upon every Chief Minister and every Education Minister, but they gave the invariable answer 'You are prepared to give us 50 per cent, but we have not got the other 50 per cent; so, we cannot do it'.

श्रीमती जमुना देवी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मध्य प्रदेश शासन ने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

Shri M. C. Chagla: In regard to Madhya Pradesh, the position is as follows. As regards revision of pay scales, the State Government have revised the pay scales of private primary school teachers at a cost of Rs. 9 crores, which has taken away a big slice from the educational plan. This is the answer that I have received after I wrote to the Chief Minister of Madhya Pradesh, namely that they have already revised the scales, and this has cost them Rs. 9 crores, and they have no more money to improve the scales further.

Shrimati Yashoda Reddy: Is the Minister in a position to indicate the maximum and minimum pay scales given to primary school teachers in various States?

Shri M. C. Chagla: It varies from State to State. Andhra Rs. 80-150; Assam Rs. 55-75; Bihar Rs. 50-90; Gujarat Rs. 56-70; Jammu and Kashmir Rs. 70-160; Kerala Rs. 40-120; Madhya Pradesh which is good, 90-170; Madras which is good, 90-140; Maharashtra Rs. 56-70; Mysore Rs. 80-150; Orissa, which is excellent, Rs. 100-155; Punjab—which is very good, perhaps the best in India—I compliment that State—Rs. 120-175; Rajasthan Rs. 75-160 and U.P., which is the worst, Rs. 50-65, and then West Bengal Rs. 80-150.

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय जिस श्रेणी को अंग्रेजी के अध्यापक पढ़ाते हैं उसी श्रेणी को संस्कृत के अध्यापक भी पढ़ाते हैं, पर अंग्रेजी के अध्यापकों और संस्कृत के अध्यापकों के वेतन मान में महान् अन्तर है । मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ।

Shri M. C. Chagla: I am always prepared to answer questions, but I do not think this arises from the original question. I would like to have notice.

Shri Jashvant Mehta: The hon. Minister has stated that different scales prevail in different States. In his letter to the Chief Ministers, did the hon. Minister suggest any common pay scale all over the country? Is Government considering having it in the Fourth Plan a uniform pay scale all over the country for primary teachers? If so, what are the details and is the Central Government prepared to subsidise the States or help them in giving primary school teachers such scales?

Shri M. C. Chagla: I think I have already mentioned that the Central Government is prepared to subsidise the increase in teachers' salaries to the extent of 50 per cent.

As regards laying down a common scale of pay, it is very difficult to do so. Conditions vary from State to State, as I pointed out. In Punjab, it starts with 120; in U.P. it starts with Rs. 50....

Shri Tyagi: Not by names.

श्री राम सेवक यादव : मंत्री महोदय ने बताया कि केन्द्र ने 50 प्रतिशत धन अध्यापकों की स्थिति सुधारने के लिए देने का निश्चय किया है लेकिन राज्यों के पास और अतिरिक्त 50 प्रतिशत धन नहीं है, इसलिए यह स्काम चालू नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षामंत्रालय यह 50 प्रतिशत रकम राज्य सरकारों को शीघ्र देने के लिए तैयार है ताकि अध्यापकों की स्थिति में कुछ तो सुधार हो जाए ?

Shri M. C. Chagla: We cannot because the scheme is, 'If you raise the salaries, tell us how much it will cost; we will bear half of it'. I do not see how we can give a part when they are not prepared to make any contribution.

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि जबसे केन्द्र ने इस बात पर बल देना शुरू किया है कि प्राथमिक शिक्षकों के वेतन मान में सुधार हो और राज्यों को उनका वेतन बढ़ाने का संकेत किया है, उसके बाद से किन किन राज्यों ने सिद्धान्त रूप में या कार्य रूप में अथवा दोनों रूप में इसको मान लिया है और क्या उसके फल-स्वरूप कुछ भी उनके वेतन मान में वृद्धि हुई है ?

Shri M. C. Chagla: I think I gave the answer to that. In reply to my letter to all Chief Ministers, I received only four letters, from four States. No replies were received from other States. Many of the State scales are already high, and, therefore, perhaps they did not think it necessary to reply to my letter.

श्री के० डी० मालवीय : जब सरकार को यह मालूम हो गया है कि खत लिखने से और कानफरेंसें करने से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शिक्षकों के वेतनों में वृद्धि नहीं हो रही है, तो क्या सरकार कोई और भी तरीका अख्तियार करने को तैयार है जिससे कि यह जरूरी मसला हल हो सके ?

श्री मु० क० चागला : अगर मेरे दोस्त मुझे बतायेंगे कि किस रीति से यह कर सकता हूं तो मैं उनका आभारी होऊंगा ।

Shri K. D. Malaviya: You give direction to planning.

Shrimati Renuka Ray: I wanted to ask the Minister, in view of the fact that even the salary which is considered minimum is not paid by some of the States, whether the Central Government would not consider that any educational grants, whether it be for higher education or secondary education or any other education, will not be given to a State Government that does not give at least a minimum of Rs. 90, to a primary teacher since labourers get Rs. 90 a month.

Shri M. C. Chagla: In the Fourth Plan, we are trying to revise the whole system of educational finance, and we are trying to consider the question of these matching grants. So, I will bear this in mind.

Shri Sheo Narain: The hon. Minister has said that U.P. is the worst State. Considering this, what is he going to do now?

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: What are the chief reasons the hon. Minister finds for the conspicuous failure in his home State?

Shri M. C. Chagla: Maharashtra is not so bad. It is pretty bad. It is Rs. 56 to Rs. 70, which, I agree, is not very good, but the dearness allowance is high.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Economic Pool

*353. **Dr. L. M. Singhvi:**
Shri Indrajit Gupta:
Shri Yashpal Singh:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri K. C. Pant:
Shri S. M. Banerjee:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 120 on the 3rd June, 1964 and state:

(a) whether any decision has been taken regarding the formation of an Economic Pool for staffing various managerial positions in the public sector undertakings; and

(b) in what manner the selection and recruitment to this pool would be regulated?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). The matter is still under consideration.